

प्रधान मंत्री की ब्रिटेन यात्रा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : PRIME MINISTER'S VISIT TO U. K.

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री हेरोल्ड विल्सन के निमंत्रण मैंने 3 से 6 दिसम्बर 1964 तक लंदन की यात्रा की ब्रिटेन में मेरा यह दौरा थोड़े समय का ही था किन्तु यह निस्सन्देह फायदेमन्द रहा।

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों से मिलने से पूर्व मुझे वहां की महाराणी से भी मिलने का मौका मिला।

श्री हेरोल्ड विल्सन और उनके अन्य सहयोगियों के साथ मुलाकात के दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई। हमने मंत्री-पूर्ण और अनौपचारिक बातावरण में अपने विचारों का खुलकर आदान प्रदान किया। चर्चा के लिए कोई रस्मी विषय-सूची नहीं थी। फिर भी हमने निम्नलिखित विषयों पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया :—

(i) जटिल अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, हमारी निगाह में तथा उनकी निगाह में, विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और अफ्रीका में।

(ii) शान्ति, निरस्त्रीकरण विशेषकर परमाणु निरस्त्रीकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ, बहुपक्षीय सेना, शेष उपनिवेशों के लिए आजादी तथा विकासप्रणित देशों के लिए सहायता कार्यक्रमों सम्बन्धी समस्याएं।

(iii) ब्रिटेन की भूगतन-शेष समस्या।

(iv) भारत के विकास कार्यक्रम तथा भारत की प्रतिरक्षा आवश्यकताएं।

जैसे कि सभा को मालूम है मैं कोई विशेष प्रार्थना अथवा प्रस्ताव लेकर ब्रिटेन नहीं गया था। फिर भी विचारों का आदान प्रदान लाभदायक रहा। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री तथा उनके सहयोगियों ने एक दूसरे का दृष्टिकोण जानने के लिए प्रायः अनौपचारिक रूप से विभिन्न स्तरों पर विचारों के आपसी आदान प्रदान के महत्व पर जोर दिया यद्यपि कुछ विशिष्ट मामलों पर हमारे बीच मतभेद ही क्यों न हों, उनका विचार था कि विश्व की पेचीदा और कठिन स्थिति में इस प्रकार की वैयक्तिक चर्चा विश्व शान्ति और निरस्त्रीकरण के हित में होगी और इस से विश्व की, विशेषकर विकासशील देशों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी सहायता मिलेगी।

एक बात जोकि हमारी विशेष दिलचस्पी की है और जिस पर ब्रिटेन का भी ध्यान गया है चीन द्वारा हाल में किया गया अणु विस्फोट तथा भारत सरकार की अणुशक्ति स्थिति पर इसका प्रभाव है। इस विषय पर हमारे विचार स्पष्ट हैं। भारत शान्ति के मार्ग पर चलता रहेगा और परमाणु खतरे के उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील रहेगा। जिन देशों के पास परमाणु अस्त्र नहीं हैं उनके इस मामले पर विशेष ध्यान देना है और भारत सरकार इस विषय में और सरकारों के साथ सम्बन्ध बढाए रखी है। इसके साथ ही यह अमरिका और रुस जैसी बड़ी बड़ी परमाणु शक्तियों की जिम्मेदारी है कि वह इस खतरे के निराकरण के लिए ठोस उपाय सोचें। हमें यह भूल न जाना चाहिये कि परमाणु अस्त्रों का खतरा समस्त मानव जाति के लिये है। हमने अपने विचार निश्चित रूपसे व्यक्त किये और उन्होंने उनका स्वागत किया।

ब्रिटेन की सरकार तथा नेताओं की भारत के प्रति जो मैत्री की भावना है उस से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ।

मैंने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री तथा श्रीमती विल्सन को भारत आने का निमंत्रण दिया है और उन्होंने उसे स्वीकार किया है। हमें उनके आगमन की प्रतीक्षा है।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Whether the question was considered that if China did not desist from making the atom bombs, what action should be taken ?

Shri Lal Bahadur Shastri : I have already said as to what was the way out. But the real remedy was that we should not allow China use her atom bomb power.

श्री स्वैल (आसाम स्वायत्त शासी जिले) : समाचार है कि प्रधान मंत्री ने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री को सुझाव दिया है कि अफ्रिका और रूस जैसी परमाणु शक्तियों द्वारा गर-परमाणु देशों को किसी देश द्वारा किये गए परमाणु हमले के विरुद्ध एक तरह की गारंटी दी जानी चाहिये। क्या यह सुझाव देने से पूर्व सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका की राय का पता लगाया था ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnore) : May we know whether the Prime Minister held any consultations with the British Prime Minister on the Kashmir issue ? If so, what was their view point in the matter ?

Shri Lal Bahadur Shastri : There was no particular discussion on the subject, but when they broached the issue I placed the Government of India's view point before them. They had nothing to say further on the subject.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : का प्रधान मंत्री का ध्यान ब्रिटेन के राष्ट्र मंडलीय सचिव के इस व्यक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत को सैनिक सहायता देते समय ब्रिटेन ने तीन शर्तें लगा दी हैं और उनमें से एक शर्त यह है कि ब्रिटेन को इस बात का अधिकार होगा कि वह भारत को दिये गये हथियारों का निरीक्षण करें और ब्रिटिश हाईकमीशन के अधिकारी यह काम करेंगे ? यदि हां, तो क्या इस विषय पर भी बातचीत हुई है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे खेद है कि मैंने श्री बाटमाले का वह व्यक्तव्य नहीं पढ़ा है। यदि उन्होंने ऐसी कोई बात कही हो तो हम ब्रिटेन की सरकार के साथ इस पर बातचीत करेंगे।

श्री जसवन्त मेहता (भावनगर) : प्रधान मंत्री ने परमाणु शक्तियों वाले देशों द्वारा गर-परमाणु देशों को परमाणु खतरे से बचाने के लिये गारंटी देने के बारे में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री की प्रतिक्रिया का पता लगाया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : ब्रिटेन के प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में कोई निश्चित बात नहीं कह सके हैं लेकिन उनका विचार था कि परमाणु शक्ति वाले देशों को ऐसे उपाय ढूँढने चाहिये जिस से कि गर-परमाणु शक्ति वाले देश किसी खतरे में न रहे अथवा जिस से कि चीन या दूसरे अणुशक्ति वाले देशों का खतरा घट जाये।

श्री नाथ पाई (राजापूर) : क्या प्रधान मंत्री का यह विचार था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस एक ऐसा संयुक्त अणुशक्ति संरक्षण प्रदान करें जिससे कि उन देशों का खतरा घट जाये जिनके पास अणुअस्त्र नहीं हैं ? क्या श्री विल्सन ने श्री जानसन के साथ इस पर चर्चा करने की बात कही थी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के पहले भाग में जो कुछ कहा है वह अधिकांश रूप से सही है, मैंने संरक्षण अथवा ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया लेकिन मैंने यह कहा था कि परमाणु-शक्ति वाले देशों की यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसे उपायों पर विचार करें जिनसे कि अणु-अस्त्रों का खतरा कम हो जाये। जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है इस बात का फैसला करना ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का काम है। उन्होंने मुझे ऐसी कोई बात नहीं कही।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बेरकपूर) : क्या प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रस्ताव दिया था कि परमाणु अस्त्रों के निर्माण को अन्त करने तथा अस्त्र भण्डारों के नाश के उद्देश्य से परमाणु परीक्षण रोक सन्धि को और व्यापक करके फ्रांस और चीन पर भी लागू किया जाये ? क्या उन्होंने ने ऐसा कोई प्रस्ताव श्री विल्सन के सामने रखा था ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैंने उन्हें सुझाव दिया कि परमाणु परीक्षण रोक संधि को और बढ़ा दिया जाये लेकिन दूसरे तरीके से। अर्थात् यह कि भूमिगत परीक्षण भी बंद हो आदि। निस्सन्देह इसका मतलब यह भी होगा लेकिन मैंने इसका जिक्र नहीं किया कि चीन और फ्रांस को भी मास्को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये अपील की जाये। लेकिन मैंने वह सुझाव नहीं दिया।